NYCS
RNI: DELBIL/2008/25219, ₹20

युवा सहकार

www.nycsindia.com
नवंबर 2025, नई दिल्ली

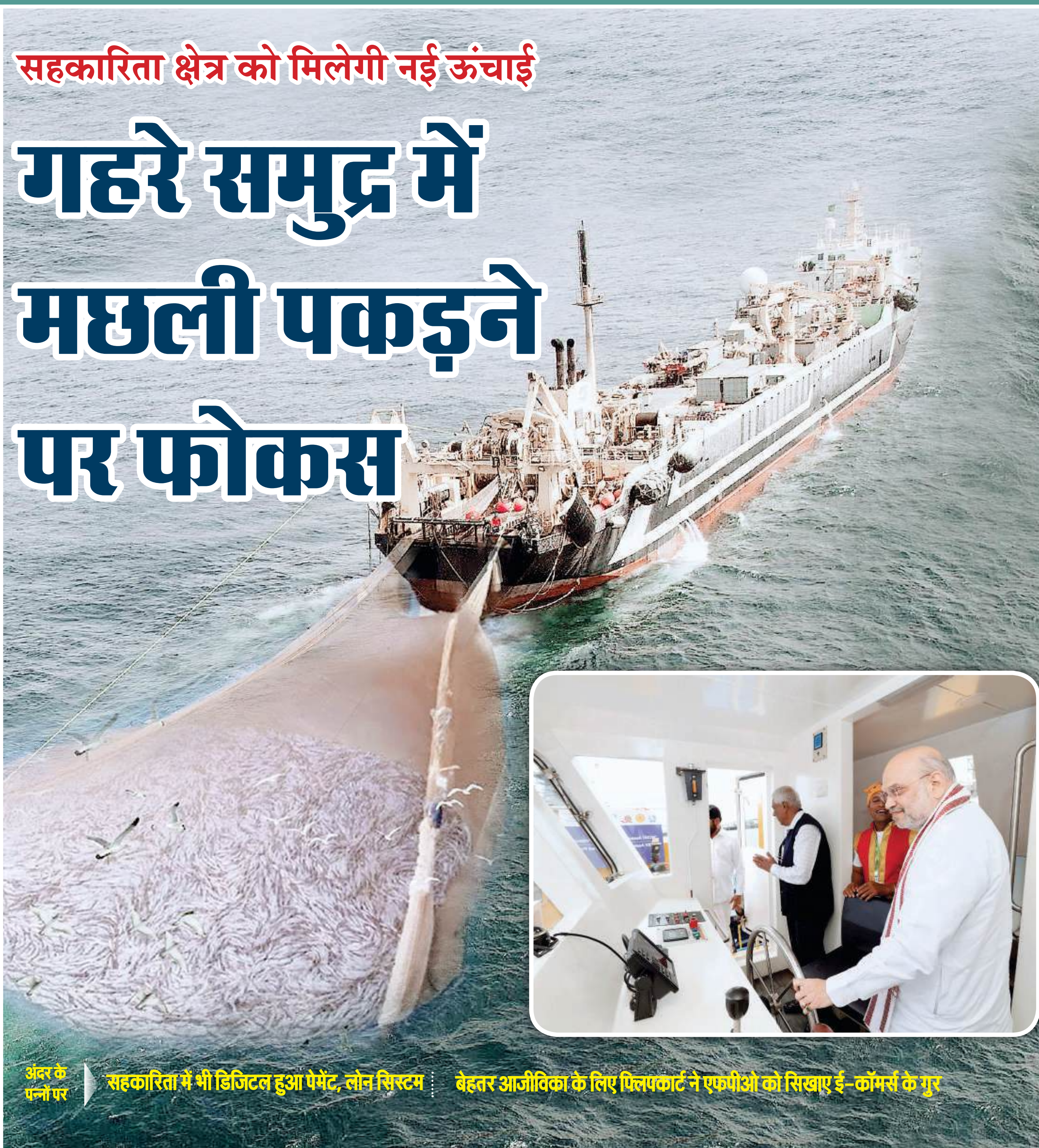

सहकारिता क्षेत्र को मिलेगी नई ऊंचाई

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर फोकस

अंदर के पन्नों पर
सहकारिता में भी डिजिटल हुआ पेमेंट, लोन सिस्टम
बेहतर आजीविका के लिए फ्लिपकार्ट ने एफपीओ को सिखाए ई-कॉमर्स के गुर

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

KRIBHCO
Cooperative and beyond...

SERVING **FARMERS**
TO GROW BOUNTIFUL

KRIBHCO world's premier fertilizer producing cooperative has been consistently making sustained efforts towards promoting modern agriculture and cooperatives in the country. It helps farmers maximize their returns through specialised agricultural inputs and other diversified businesses.

KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LTD

Registered Office: A-60, Kailash Colony, New Delhi-110048 | **Phone: 011-29243412**
Corporate Office: KRIBCHO BHAWAN, A 8-10, Sector-1, Noida-201301, Distt: Gautam Budh Nagar (UP) | **Phones:** 0120-2534631/32/36
Website: www.kribhco.net | **KRIBCHO Kisan Helpline:** 0120-2535628 | **E-mail:** krishipramarsh@kribhco.net

OUR PRODUCTS
Neem Coated Urea | DAP | MOP | NPK | NPS | MAP | Liquid Bio Fertilizers | Certified Seeds | Hybrid Seeds
City Compost | Zinc Sulphate | Natural Potash | Sivarika | Rhizosuper

युवा सहकार

वर्ष : 02, अंक-05, नवंबर-2025

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता
दर्शन सोलंकी (विशेष आमंत्रित)
देवेन्द्र सिंह (विशेष आमंत्रित)
रामचंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी (सीईओ)

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: **nycs.ltd@gmail.com**
Web: **www.nycsindia.com**

Registration No DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं मित्तल प्रिंट एन पैक, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-92 द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमारः पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

कोऑपरेटिव से मजबूत होगी ब्लू इकोनॉमी 04
इफको को पछाड़ नंबर 1 बनी अमूल 05

06 गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर फोकस

16 युवाओं को कोऑपरेटिव्स से जोड़ने के लिए जागरूकता बढ़ाना जरूरी

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग से रोजगार बढ़ाने की पहल 14
सहकारिता में भी डिजिटल हुआ पेमेंट, लोन सिस्टम 18
बेहतर आजीविका के लिए फ्लिपकार्ट ने एफपीओ को सिखाए ई-कॉमर्स के गुर 22
पीएम सेतु से उन्नत होंगे आईटीआई 25
छोरियों ने दिखाया गिर कर उठना 27
संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक 30

कोऑपरेटिव से मजबूत होगी ब्लू इकोनॉमी

अगर गहरे समुद्र का दोहन पर्याप्त रूप से हो जाता है तो भारत विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक और निर्यातक बन सकता है। नए नियमों के लागू होने, सुविधाओं के विस्तार और ट्रॉलर की उपलब्धता से न केवल इस क्षेत्र से जुड़े 3 करोड़ मछुआरे आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि भारत वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबल फिशिंग मॉडल के रूप में अपनी पहचान को और सुदृढ़ करेगा। यह कदम भारत की ब्लू इकॉनॉमी को मजबूत करेगा और सहकारिता क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

भारत का विशाल समुद्री क्षेत्र 23 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जहां मछली पकड़ने की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। अभी सिर्फ 12 समुद्री मील तक ही मछुआरे मछली पकड़ने जा पाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बड़े जहाजों जिन्हें ट्रॉलर कहा जाता है, का अभाव है। सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से मछुआरों को ट्रॉलर उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। अगले पांच वर्ष में ऐसे 200 ट्रॉलर उपलब्ध कराने की योजना है जिससे न सिर्फ मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि हाशिये पर रहने वाले मछुआरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। ये ट्रॉलर 25 दिनों तक गहरे समुद्र में रहकर 20 टन तक मछली पकड़ सकते हैं। इन ट्रॉलर की कीमत करोड़ों में होती जिसके लिए एनसीडीसी वित्तीय मदद मुहैया कराएगी। सहकारी समितियों द्वारा इनकी खरीद पर सरकार सब्सिडी भी देगी। इन ट्रॉलर का निर्माण देश में ही होगा।

समुद्री संसाधनों के दोहन और मछुआरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नए नियम भी लागू किए हैं। नए नोटिफिकेशन में समुद्री सीमा को बढ़ाकर 11,099 किलोमीटर तय किया गया है। इससे भारतीय मछुआरे अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) में 200 समुद्री मील तक मछली पकड़ने जा सकेंगे। समुद्री जल क्षेत्रों का भारत ने अभी तक पूरी क्षमता से उपयोग नहीं किया है। विशेष रूप से टूना जैसी ज्यादा कीमत वाली मछलियों के उत्पादन में भारत पिछड़ा हुआ है, जबकि श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया जैसे देश इन संसाधनों का व्यापक उपयोग करते रहे हैं।

केंद्र सरकार ने नए नियम मछुआरों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए हैं। इसके तहत मछली पकड़ने वाले विदेशी जहाजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है ताकि देश के मछुआरों और सहकारी समितियों को इसका सीधा लाभ मिल सके। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने मछली पकड़ने वाले जहाजों को समुद्र के बीच में ही लेन-देन करने की अनुमति दे दी है। इससे परिवहन लागत में कमी आएगी और मछुआरों को उचित दाम सुनिश्चित होंगे। सरकार ने एक पोर्टल भी शुरू किया है जिसके माध्यम से मछुआरे एक्सेस पास प्राप्त कर सकेंगे। यह पास उन जहाजों के लिए अनिवार्य है जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं। इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है ताकि मछुआरों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके अलावा भी समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों के लिए कई अन्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है।

भारत आज मछली उत्पादन के मामले में चीन और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है और हर साल लगभग 60,000 करोड़ रुपये के समुद्री उत्पाद का निर्यात करता है। वह भी तब जब समुद्री संसाधनों का दोहन ठीक से नहीं हो पाया है। अगर गहरे समुद्र का दोहन पर्याप्त रूप से हो जाता है तो भारत विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक और निर्यातक बन सकता है। नए नियमों के लागू होने, सुविधाओं के विस्तार और ट्रॉलर की उपलब्धता से न केवल इस क्षेत्र से जुड़े 3 करोड़ मछुआरे आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि भारत वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबल फिशिंग मॉडल के रूप में अपनी पहचान को और सुदृढ़ करेगा। यह कदम भारत की ब्लू इकॉनॉमी को मजबूत करेगा और सहकारिता क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।■

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

इफको को पछाड़ नंबर 1 बनी अमूल

आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट में भारतीय कोऑपरेटिव को मिला यह दर्जा

युवा सहकार टीम

देश की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (जीसीएमएमएफ), जो अमूल ब्रांड की मालिक है, अब दुनिया की नंबर एक कोऑपरेटिव बन गई है। इसने भारत की ही दिग्गज फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफको को पछाड़ कर यह स्थान हासिल किया है। इफको अब दूसरे नंबर पर खिसक गई है। इससे पहले लगातार तीन साल तक इफको दुनिया की नंबर एक कोऑपरेटिव रही थी। अमूल और इफको का यह सम्मान भारतीय सहकारी आंदोलन के लिए एक मील का पत्थर है। यह न केवल किसानों की मेहनत और आत्मनिर्भरता की जीत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि 'सहकार से समृद्धि' का भारतीय मॉडल आज भी विश्व के लिए प्रेरणा बना हुआ है।

विश्वभर की सहकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) द्वारा जारी वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट में अमूल को प्रति व्यक्ति जीडीपी प्रदर्शन के आधार पर दुनिया की नंबर-1 कोऑपरेटिव का दर्जा मिला। आईसीए ने यह रिपोर्ट कतर के दोहा में आयोजित आईसीए सीएम 50 कॉन्फ्रेंस में जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमूल की यह उपलब्धि उसकी लगातार वृद्धि, नवाचार और पीपुल फर्स्ट की भावना पर आधारित व्यावसायिक दृष्टिकोण का परिणाम है। इसी सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का औपचारिक समापन भी किया गया। सम्मेलन में सहकारी नेताओं ने यह निर्णय भी लिया कि हर 10 वर्ष में एक बार अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जाएगा, ताकि वैश्विक स्तर पर सहकारी मॉडल को और मजबूती दी जा सके।

अमूल और इफको की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि भारत का सहकारी क्षेत्र जीवंत है और अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। सरकार आने वाले समय में इस क्षेत्र को और प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दोनों संस्थाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह भारत के लिए गर्व का पल है। यह अमूल से जुड़ी लाखों महिलाओं के अथक समर्पण और इफको में योगदान देने वाले किसानों के लिए सम्मान की बात है। यह उपलब्धि सहकारी संस्थाओं में असीम संभावनाओं का भी प्रमाण है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता के वैश्विक मॉडल के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं।

जीसीएमएमएफ के एमडी जयेन मेहता ने कहा कि अमूल पूरी तरह किसानों की स्वामित्व वाली संस्था है। दूध संग्रह से लेकर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तक का सारा काम किसान ही संभालते हैं। हमारा मॉडल सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि यह गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता और सतत समुदायों के विकास जैसे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के कई लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाता है। अमूल की असली पूंजी दूध नहीं, बल्कि करोड़ों उत्पादकों और अरबों उपभोक्ताओं का भरोसा है। यह सम्मान न सिर्फ अमूल परिवार के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि भारत के सहकारी आंदोलन की शक्ति और हमारे संस्थापकों की सामूहिक समृद्धि की दृष्टि का प्रमाण भी है।

आईसीए का मुख्यालय ब्रसेल्स में है, जो विश्वभर की सहकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है और स्थायी व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करता है। हर साल जारी होने वाली वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट को यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइज (EURICSE) के सहयोग से तैयार किया जाता है। यह रिपोर्ट दुनिया की प्रमुख सहकारी संस्थाओं के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण करती है।■

- पर्याप्त गहरे समुद्री दोहन से भारत बन सकता है विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक और निर्यातक, सहकारिता क्षेत्र की बढ़ेगी भूमिका
- भारत के 11,098 किलोमीटर विशाल समुद्री जल सीमा के दोहन की केंद्र सरकार ने बनाई योजना
- गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बड़े जहाजों (ट्रॉलर) से लैस होंगी मछुआरों की सहकारी समितियां
- एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) में 12 समुद्री मील से आगे 200 समुद्री मील तक पकड़ी जाएंगी मछलियां
- आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रॉलर्स 25 दिनों तक गहरे समुद्र में पकड़ सकते हैं मछलियां
- अगले पांच वर्षों में देश भर में सहकारी मछुआरा सोसायटियों को एनसीडीसी की वित्तीय मदद से दिए जाएंगे 200 ट्रॉलर

सहकारिता क्षेत्र को मिलेगी नई ऊंचाई

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर फोकस

युवा सहकार टीम

मत्स्य क्षेत्र भारत का उभरता हुआ क्षेत्र है जो ग्रामीण और समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों, खासकर मछुआरों और मछली पालकों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास की आधारशिला है। इस क्षेत्र से लगभग 3 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। चीन और इंडोनेशिया के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। वैश्विक मछली उत्पादन में इसका 8 प्रतिशत योगदान है। विश्व स्तर पर जलीय कृषि उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और यह शीर्ष झींगा उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। जबकि मछली और मत्स्य उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। यह सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बावजूद गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के मामले में इसकी भागीदारी लगभग नगण्य है। भारत की लंबी समुद्र तटीय और गहरे समुद्र की जल सीमा में मछली पकड़ने की अपार संभावनाएं हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय इन संभावनाओं का दोहन करने की विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहा है। इनमें प्रमुख है, मत्स्य क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचों का निर्माण करना और मत्स्य सहकारी समितियों को मछली पकड़ने के बड़े जहाज (ट्रॉलर) उपलब्ध कराना। अभी देश में इनका अभाव है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मुंबई के मझगांव डॉक में बनी दो ट्रॉलर की चाबियां मछुआरों को सौंपी है। ये ट्रॉलर 25 दिन तक गहरे समुद्र में रह कर 20 टन तक मछली पकड़ सकते हैं। अगले पांच वर्ष में ऐसे 200 ट्रॉलर मत्स्य सहकारी समितियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इनका निर्माण मझगांव डॉक पर ही किया जाएगा। इससे न सिर्फ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में तेजी आएगी, बल्कि मछली उत्पादन और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे जिससे इस क्षेत्र से जुड़े लोग, खासकर हाशिये पर रहने वाले मछुआरे आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकेंगे। इस पहल के जरिये सहकारिता मंत्रालय मौजूदा तटीय इलाके में मछली पकड़ने (12 समुद्री मील के भीतर) के अलावा मत्स्य सहकारी समितियों को भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) में 12 समुद्री मील से आगे 200 समुद्री मील तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकल्प को अपनाने पर फोकस कर रहा है। इच्छुक मत्स्य सहकारी समितियां राज्य सहकारी संघ और राष्ट्रीय मत्स्य सहकारी महासंघ (FISHCOPFED) की सहायता से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और अन्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से मछली पकड़ने के लिए ट्रॉलर खरीदने और तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए वित्त पोषण प्राप्त कर सकती हैं।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का मिल रहा लाभ

मछली उत्पादन बढ़ाने और युवाओं के लिए इस क्षेत्र में नए अवसर बनाने में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) का उद्देश्य मछली उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, मत्स्य उत्पादन के बाद की अवसंरचना और प्रबंधन, आधुनिकीकरण और मूल्य शृंखला को मजबूत करने पर ध्यान देना है। इस योजना के तहत लाभार्थी कुल परियोजना लागत एवं इकाई लागत का 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मत्स्य पालन और जलीय कृषि बुनियादी ढांचा विकास निधि (एफआईडीएफ) का लक्ष्य समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं तैयार करना है। इस योजना में आइस-प्लांट का निर्माण, कोल्ड स्टोरेज का विकास, मछली परिवहन और कोल्ड चेन नेटवर्क बुनियादी ढांचे, ट्राउट ब्रूड बैंकों की स्थापना, हैचरी, मछली प्रसंस्करण इकाइयों, मछली चारा मिलों एवं संयंत्रों का विकास और आधुनिक मछली बाजारों का विकास शामिल है। यह योजना मछली उत्पादन में लगे सीमांत मछुआरों सहित छोटे और सीमांत किसानों को अपेक्षित फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, कौशल विकास, प्रसंस्करण और कोल्ड चेन बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे वे अपनी आय बढ़ाने में सक्षम हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) को वर्ष 2020-21 में 20,050 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया था। पीएमएमएसवाई के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में मछली पकड़ने के बंदरगाह, मछली लैंडिंग केंद्र, जलाशय पिंजरा संस्कृति, खारे और मीठे पानी की जलीय कृषि, मछुआरों का कल्याण, बुनियादी ढांचा सुविधाएं, समुद्री शैवाल, सजावटी और ठंडे पानी की मत्स्य पालन आदि परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों और मछली पालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाने के लिए मछली किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों, जैसे नीली क्रांति योजना, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएमएमकेएसएसवाई) के माध्यम से मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है।

इससे वे अधिक मछली पकड़ने, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात सुनिश्चित कर सकती हैं।

सहकारिता मंत्रालय का जोर समुद्र तटीय मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से फिशिंग, उनकी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सप्लाई चेन को बढ़ावा देने पर है। सरकार ने दो लाख नई प्राथमिक सहकारी समिति (पैक्स) बनाने का जो लक्ष्य तय किया है उसके तहत मत्स्य क्षेत्र में 11 हजार नए पैक्स बनाए जा रहे हैं। इनके जरिये मछुआरों को सशक्त बनाया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों, जैसे नीली क्रांति योजना, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएमएमकेएसएसवाई) के माध्यम से मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है। अब तक 38,572 करोड़ रुपये का कुल निवेश इस क्षेत्र में किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने 2,000 मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का गठन शुरू किया है, मत्स्य पालन क्लस्टर विकसित किए हैं और प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण और बाजार संपर्कों को एकीकृत करने के लिए एक्वा पार्क पर काम हो रहा है।

इसी कड़ी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजना को अमलीजामा पहनाने का काम शुरू किया गया है। इस क्षेत्र के पर्याप्त दोहन से अगले कुछ वर्षों में भारत न सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक बन सकता है, बल्कि निर्यात के मामले में भी यह शीर्ष पर पहुंच सकता है। सरकार के ठोस प्रयासों से समुद्र तटीय इलाकों के मछुआरों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। मत्स्य क्षेत्र पिछले एक दशक में 7 प्रतिशत से अधिक की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। 11,098 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा, 68.79 लाख हेक्टेयर अंतर्देशीय जल निकायों (जलाशय, तालाब और टैंक आदि) और 1,95,000 किलोमीटर लंबी नदियों के साथ भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और विविध मत्स्य संसाधनों में से एक है। इसके बावजूद यह क्षेत्र चुनौतियों से जूझ रहा है।

चुनौतियां और समाधान

इसकी प्रमुख चुनौतियों में बिखरी हुई संरचना, असंगठित संचालन, सामूहिक सौदेबाजी की कमी, फाइनेंस की असुविधा, आधुनिक तकनीक का अभाव, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, विशेष रूप से मूल्य संवर्धन एवं कोल्ड स्टोरेज का अभाव, कुशल प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण और मार्केटिंग की कमी शामिल है। जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ी चुनौती है जिसका प्रभाव अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन दोनों पर पड़ता है। इससे मछलियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है जिससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इन चुनौतियों का समाधान मत्स्य सहकारी समितियों, एफएफपीओ, शोध संस्थानों एवं टेक्नोलॉजी सेंटर जैसे संबद्ध निकायों का एकीकरण कर रणनीति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सामूहिक कार्रवाई, डिजिटल प्लेटफॉर्म और संस्थागत तालमेल का लाभ उठाकर ये संगठन इस क्षेत्र में लचीलापन, उत्पादकता और समान विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही, मूल्य संवर्धन और मछली प्रसंस्करण में निवेश बढ़ाकर मछलियों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तार, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम अपनाना और मूल्यवर्धित उत्पादों

(रेडी-टू-ईट, फ्रोजन फिलेट्स आदि) में विविधता लाकर निर्यात राजस्व को कई गुना बढ़ाया जा सकता है।

सहकारिता दूर करेगा संकट

मत्स्य क्षेत्र की मौजूदा 28,226 प्राथमिक सहकारी समितियों में 39.66 लाख मछुआरे सदस्य हैं। जबकि 11 हजार नई सहकारी समितियां और बनाई जा रही हैं। ये सहकारी समितियां बिखराव को दूर करने, सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए एक सामूहिक शक्ति के रूप में कार्य कर सकती हैं। मछुआरा परिवारों को एफएफपीओ के माध्यम

मत्स्य क्षेत्र पिछले एक दशक में 7 प्रतिशत से अधिक की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। 11,098 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा, 68.79 लाख हेक्टेयर अंतर्देशीय जल निकायों और 1,95,000 किलोमीटर लंबी नदियों के साथ भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और विविध मत्स्य संसाधनों में से एक है।

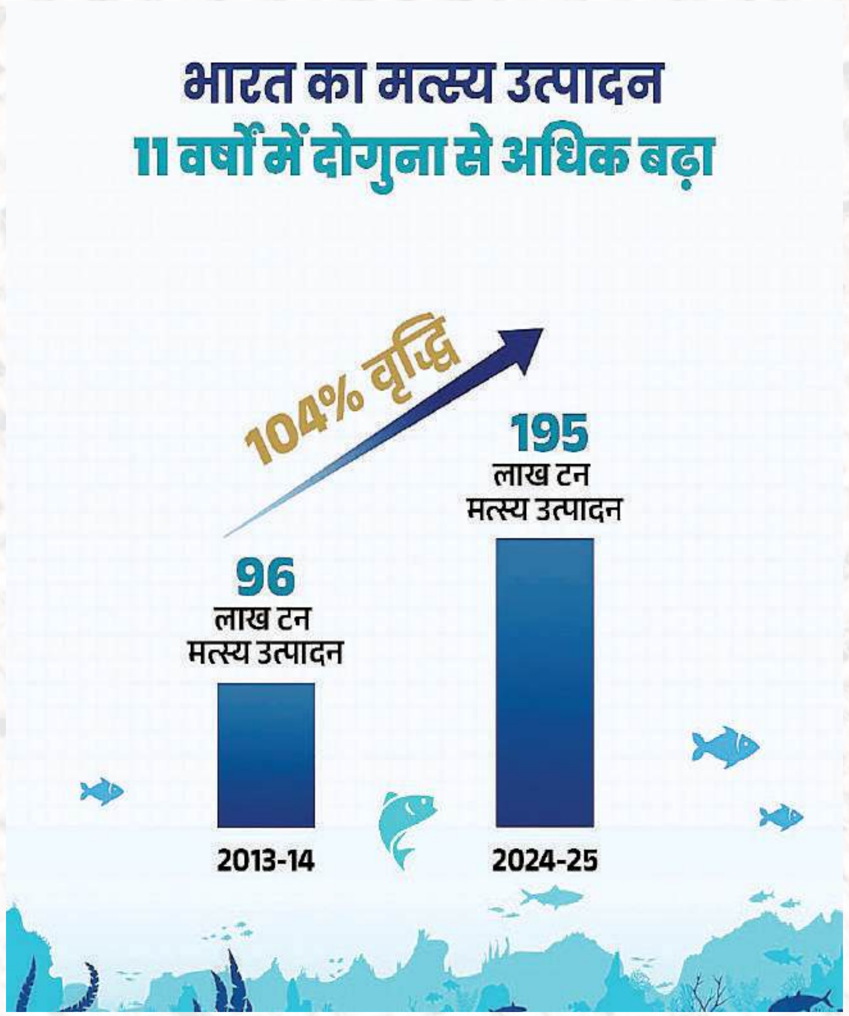

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के अलावा मत्स्य सहकारी समितियां अपने सदस्यों को जलीय कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए मछली बीज की आपूर्ति करने हेतु छोटी हैचरी या नर्सरी स्थापित करने में मदद कर सकती हैं।

से संगठित करने के अलावा स्वयं सहायता समूहों को मत्स्य सहकारी समितियों के तौर पर औपचारिक रूप देने की अपार संभावनाएं हैं। एक सुदृढ़ और एकीकृत सहकारी मॉडल मछुआरों, जलीय कृषि कृषकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, इनपुट आपूर्तिकर्ताओं, वित्तीय संस्थानों और बाजार के हितधारकों को एक छत के नीचे लाता है, जिससे इस क्षेत्र का समग्र विकास संभव होता है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के अलावा मत्स्य सहकारी समितियां अपने सदस्यों को जलीय कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए मछली बीज की आपूर्ति करने हेतु छोटी हैचरी या नर्सरी स्थापित करने में मदद कर सकती हैं। झींगा की मांग घरेलू और वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती जा रही है। मत्स्य सहकारी समितियां सामूहिक रूप से झींगा पालन को बढ़ावा देकर अपने सदस्यों को समृद्ध बना सकती हैं। इसी तरह, सजावटी मछली पालन कम निवेश में ज्यादा मुनाफा कमाने वाला उभरता हुआ व्यवसाय है जो विशेष रूप से युवाओं को आकर्षित कर रहा है। समुद्री शैवाल की खेती भी मुनाफे वाली है जिसे मत्स्य सहकारी समितियां अपना सकती हैं। समुद्री शैवाल का इस्तेमाल खाद्य, फार्मास्युटिकल्स और सौंदर्य प्रसाधनों में होता है। मछली पालन और मछली पकड़ने के अलावा सहकारी समितियां मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण, कोल्ड चेन और भंडारण सेवाएं, पारिस्थितिकी पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन, डिजिटल और सहकारिता संचालित पहल के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लोगों का सशक्तीकरण कर सकते हैं।

जहां तक समुद्री मत्स्य पालन का संबंध है, मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों के आसपास और अंतर्देशीय क्षेत्र में जलाशयों, झीलों, सिंचाई टैंकों आदि जैसे बड़े जल क्षेत्रों के आसपास सहकारी समितियों को संगठित करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 3 करोड़ सक्रिय मछुआरों को सहकारिता के दायरे में लाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। मत्स्य सहकारी समितियों को योजनाबद्ध तरीके से संगठित किया जा रहा है। इसके लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स को दिए जा रहे समर्थन की तर्ज पर नीतिगत सहयोग भी शामिल है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संघों के सहयोग से फिशकॉपफेड सभी निष्क्रिय मत्स्य सहकारी समितियों को समयबद्ध तरीके से पुनर्जीवित करने, उन्हें वित्तीय और व्यावसायिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है।

कुशल पेशेवरों की जरूरत

गहरे समुद्र से मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए मछुआरा नेतृत्व को सशक्त और सहकारी समितियों को पेशेवरों की आवश्यकता है।

सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों और मत्स्य प्रशिक्षण संस्थानों में कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम से कम 20 प्रतिशत मत्स्य सहकारी समितियों के लिए निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें मत्स्य पालन और सहकारी प्रबंधन के सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जिसमें व्यवसाय योजना विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मत्स्य सहकारी प्रबंधन आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय के 20 सहकारी प्रशिक्षण एवं शैक्षिक संस्थान, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एवं इसके सहयोगी संस्थान, नाबार्ड एवं इसके प्रशिक्षण संस्थान तथा मत्स्य विभाग के प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक संस्थान, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) के अन्य प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान उभरती आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण एवं प्रशिक्षण मॉड्यूलों की समीक्षा कर मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक राष्ट्रीय मत्स्य सहकारी प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की योजना भी प्रस्तावित है।

खपत और मांग में वृद्धि

भारत में घरेलू मछली की खपत में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत बढ़कर लगभग 12 किलोग्राम हो गई है, जो अभी भी वैश्विक औसत 20.5 किलोग्राम से कम है। यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में विकास की पर्याप्त संभावना मौजूद है। बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती आय और उच्च-प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव से मांग में और वृद्धि होने की उम्मीद है। मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली सरकार की विभिन्न योजनाओं की बदौलत 2024-25 में 9 प्रतिशत से अधिक की क्षेत्रीय वृद्धि दर के साथ कुल (अंतर्देशीय और समुद्री) वार्षिक मछली उत्पादन 195 लाख टन पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 184.02 लाख टन था। वित्त वर्ष 2013-14 के 95.79 लाख टन की तुलना में पिछले 10 वर्ष में उत्पादन में दोगुने से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने 60,523.89 करोड़ रुपये मूल्य के 17,81,602 टन समुद्री खाद्य पदार्थ का निर्यात किया, जो वित्त वर्ष 2013-14 के 30,213 करोड़ रुपये की तुलना में दोगुने से अधिक की वृद्धि है।■

भारत में घरेलू मछली की खपत में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत बढ़कर लगभग 12 किलोग्राम हो गई है, जो अभी भी वैश्विक औसत 20.5 किलोग्राम से कम है। यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में विकास की पर्याप्त संभावना मौजूद है। बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती आय और उच्च-प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव से मांग में और वृद्धि होने की उम्मीद है।

कवर स्टोरी

मछुआरों की समृद्धि का माध्यम बनेगी सहकारिता

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बड़े जहाजों का मझगांव डॉक पर किया लोकार्पण

अगले पांच वर्षों में देश भर में सहकारी आधार पर ऐसे 200 ट्रॉलर कराए जाएंगे उपलब्ध, खरीद के लिए एनसीडीसी से मिलेगा धन

ऐसे ट्रॉलर से मत्स्य संपदा में संभावनाओं का दोहन करने की क्षमता बढ़ेगी और इससे होने वाला मुनाफा मछुआरों में होगा वितरित

युवा सहकार टीम

आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने और कोऑपरेटिव के माध्यम से ब्लू इकोनॉमी (मत्स्य पालन, उत्पादन एवं निर्यात) को मजबूत कर गरीब मछुआरों को समृद्ध बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए बड़े जहाज (ट्रॉलर) उपलब्ध कराने की शुरुआत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत शुरुआती तौर पर मछुआरों को ऐसे दो जहाज उपलब्ध करवाए गए हैं। सरकार की योजना अगले पांच वर्षों में कोऑपरेटिव के माध्यम से ऐसे 200 ट्रॉलर उपलब्ध कराने की है। यह भारत के समुद्री मत्स्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ाने और तटीय क्षेत्रों में सहकारी नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और गहरे समुद्र में मत्स्य संसाधनों की खोज और दोहन को प्रोत्साहित करना है।

अभी देश में ऐसे जहाजों का अभाव है जिसकी वजह से गहरे समुद्र से मछली मारना असंभव है। अब इन जहाजों का निर्माण देश में ही किया जाएगा। मुंबई के मझगांव बंदरगाह पर इनका निर्माण होगा। इससे न सिर्फ जहाजों की उपलब्धता बढ़ेगी और मछली उत्पादन में तेजी आएगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अमित शाह ने पिछले दिनों मझगांव डॉक पर लाभार्थियों को दो जहाजों के पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं उनकी चाबियां सौंपी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह भारत के समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र के आधुनिकीकरण और तटीय क्षेत्रों में सहकारिता आधारित विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल भारत की ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाने और तटीय आजीविकाओं की सुरक्षा में मत्स्य सहकारी समितियों की रणनीतिक भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की इस पहल से तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। यह भारत के सी-फूड निर्यात को भी बढ़ाएगी और देश की स्थिति को वैश्विक समुद्री व्यापार में और मजबूत करेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मत्स्य सहकारी समितियों को सशक्त बनाना है, जो तटीय समुदायों के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इससे फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन्स (एफएफपीओएस) और सहकारी समितियों के विकास और विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वे आत्मनिर्भर संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकेंगी।

ये ट्रॉलर 25 दिनों तक गहरे समुद्र में रह सकेंगे और 20 टन तक मछलियां ढो सकेंगे। इनके बीच में कुछ बड़े जहाज भी रहेंगे, जो बीच से मछलियों को उठा कर किनारे तक लाएंगे। ट्रॉलर में रहने और खाने-पीने की सुविधाजनक व्यवस्था भी है। वे प्रोसेसिंग भी करेंगे, चिलिंग सेंटर भी उनके होंगे। ये ट्रॉलर काफी महंगे होते हैं। इनकी शुरुआती कीमत 8-10 करोड़ रुपये है। मत्स्य सहकारी समितियों को इनकी खरीद के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से धन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभार्थियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाएं भी प्रदान की जा रही हैं। प्रत्येक नौका की लागत 1.2 करोड़ रुपये है।

तटीय क्षेत्रों में सहकारिता आधारित विकास को बढ़ावा

सरकार मत्स्य सहकारी उद्योग को मजबूत करने और मछुआरों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए समुद्री उत्पादों के संग्रह, प्रसंस्करण और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार एक ऐसा तंत्र बनाने पर काम कर रही है जो डेयरी, चीनी मिलों और बाजार समितियों की तरह मछुआरों के लिए काम करेगा और उनकी आर्थिक समृद्धि का कारण भी बनेगा। सहकारिता मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों के जीवन का आधार बने, इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। अमित शाह ने कहा कि जिन दो ट्रॉलर का लोकार्पण हुआ है, उससे न केवल भारत की मत्स्य संपदा संभावनाओं का दोहन करने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि सहकारिता के माध्यम से मत्स्य उद्योग का मुनाफा गरीब मछुआरों के घर में पहुंचेगा। इस योजना का उद्देश्य भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और गहरे समुद्र में मत्स्य संसाधनों की खोज और दोहन को प्रोत्साहित करना है।

समुद्री क्षेत्र में अपार संभावनाएं

भारत के विशाल समुद्र तट में मछली पकड़ने की अपार संभावनाएं और क्षमताएं हैं। वर्ष 2014 में भारत का मछली उत्पादन 102 लाख टन था, जो अब 195 लाख टन तक पहुंच गया है। इसमें घरेलू जलीय उत्पादन 67 लाख टन से बढ़कर 147 लाख टन से अधिक हो गया है, जबकि समुद्री उत्पादन 35 लाख टन से बढ़कर 47 लाख टन से अधिक हुआ है। शाह ने कहा कि मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से ट्रॉलर से मछली पकड़ने का पूरा मुनाफा हर मछुआरे के घर पहुंचेगा। अभी इस तरह के 14 ट्रॉलर दिए जाएंगे। सहकारिता मंत्रालय और मत्स्य विभाग आने वाले समय में मछुआरों को और भी ट्रॉलर सहकारिता के माध्यम से प्रदान करेंगे। समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ऐसे जहाजों की खरीद के लिए आवश्यक धनराशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। ■

सरकार मत्स्य सहकारी उद्योग को मजबूत करने और मछुआरों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए समुद्री उत्पादों के संग्रह, प्रसंस्करण और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार एक ऐसा तंत्र बनाने पर काम कर रही है जो डेयरी, चीनी मिलों और बाजार समितियों की तरह मछुआरों के लिए काम करेगा और उनकी आर्थिक समृद्धि का कारण भी बनेगा।

मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग से रोजगार बढ़ाने की पहल

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) के तहत 7 परियोजनाओं के पहले चरण को मिली मंजूरी

1.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 10.34 लाख करोड़ रुपये के कंपोनेंट्स का उत्पादन और 1.42 लाख नौकरियों का होगा सृजन

युवा सहकार टीम

घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में नौकरियों के नए अवसर पैदा करने के लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) के तहत 7 परियोजनाओं के पहले चरण को मंजूरी दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है। इसके तहत मल्टी-लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी), एचडीआई पीसीबी, कैमरा मॉड्यूल, कॉपर क्लैड लैमिनेट और पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म्स भारत में ही बनेंगी।

ईसीएमएस परियोजना के तहत 1.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 10.34 लाख करोड़ रुपये के कंपोनेंट्स का उत्पादन और 1.42 लाख नौकरियों का सृजन होगा। यह भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी निवेश प्रतिबद्धता है। पहले चरण की सात परियोजनाओं में 5,532 करोड़ रुपये का निवेश होगा जिनसे 36,559 करोड़ रुपये मूल्य के कंपोनेंट्स का उत्पादन होगा और 5,100 से ज्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी। इस योजना को घरेलू और विदेशी कंपनियों की ओर से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। 249 कंपनियों ने इसके तहत निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। पहले चरण के तहत तमिलनाडु में 5, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक-एक प्रोडक्शन प्लांट की अनुमति दी गई है। यह संतुलित क्षेत्रीय विकास और महानगरों से परे हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार को मजबूत करेगा।

इन परियोजनाओं से आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू बाजार में उत्पादों की कीमतें कम होंगी। ये परियोजनाएं विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास में उच्च कौशल वाली नौकरियां सृजित करेंगी। इसके तहत रक्षा, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाई जाएंगी। यह योजना पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव) और भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) की पूरक है। यह उपकरणों से लेकर चिप्स तक, कंपोनेंट से लेकर सामग्रियों तक तथा विनिर्माण से लेकर नवाचार तक एक निर्बाध वैल्यू चेन का निर्माण करेगी।

अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इन प्लांट्स से उत्पादन के माध्यम से पीसीबी की 20 प्रतिशत और कैमरा मॉड्यूल सब-असेंबली की 15 प्रतिशत घरेलू मांग पूरी की जाएगी। साथ ही, कॉपर क्लैड लैमिनेट की मांग पूरी तरह से घरेलू स्तर पर ही पूरी की जाएगी। इन प्लांट्स से 60 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात किया जाएगा। स्वीकृत परियोजनाओं में एचडीआई पीसीबी, मल्टी-लेयर पीसीबी, कैमरा मॉड्यूल, कॉपर क्लैड लैमिनेट और पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म जैसे प्रमुख कंपोनेंट्स शामिल हैं।

कैमरा मॉड्यूल कॉम्पैक्ट इमेजिंग यूनिट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में फोटो और वीडियो कैप्चर करते हैं। भारत में इसका उत्पादन स्मार्टफोन, ड्रोन, लैपटॉप, टैबलेट, चिकित्सा उपकरण, रोबोट और ऑटोमोटिव सिस्टम में इसके उपयोग को सक्षम करेगा। एचडीआई और मल्टी-लेयर पीसीबी मुख्य सर्किट बोर्ड हैं जो हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जोड़ते और नियंत्रित करते हैं। इनका इस्तेमाल स्मार्टफोन, लैपटॉप, ऑटोमोटिव और औद्योगिक प्रणालियों में किया जाता है।

भारत पहली बार कॉपर क्लैड लैमिनेट (सीसीएल) मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगा। सीसीएल मल्टी-लेयर पीसीबी के निर्माण के लिए एक बेस कंपोनेंट के रूप में कार्य करता है। ये पीसीबी सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं। अभी इनका आयात किया जाता है। पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म कैपेसिटर के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख सामग्री है। यह कंपोनेंट उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, आईसीटी, औद्योगिक एवं विनिर्माण, दूरसंचार एवं कंप्यूटिंग उपकरणों के लिए भारत में निर्मित किया जाएगा।■

> **पहले चरण की सात परियोजनाओं में 5,532 करोड़ रुपये का निवेश होगा जिनसे 36,559 करोड़ रुपये मूल्य के कंपोनेंट्स का उत्पादन होगा और 5,100 से ज्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी। इस योजना को घरेलू और विदेशी कंपनियों की ओर से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। 249 कंपनियों ने इसके तहत निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।**

इंटरव्यू

युवाओं को कोऑपरेटिव्स से जोड़ने के लिए जागरूकता बढ़ाना जरूरी

सहकार से समृद्धि के माध्यम से भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय जो पहल कर रहा है उसमें प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण है। सहकारिता विशेषज्ञ और नीति आयोग के संयुक्त सचिव **कमल कुमार त्रिपाठी** सहकारिता क्षेत्र का भविष्य संवारने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। सहकारिता मंत्रालय के गठन की ढांचागत संरचना तैयार करने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। वह सहकारिता क्षेत्र को करीब से देखते और समझते रहे हैं। सहकारिता क्षेत्र की मजबूती के लिए उठाए कदमों का जमीन पर क्या असर दिख रहा है और आगे किस तरह की योजनाएं बनाई जाएंगी, सहित इस क्षेत्र के तमाम मुद्दों पर **एसपी सिंह** और **अभिषेक राजा** ने उनसे विस्तार से बातचीत की। पेश हैं उनके प्रमुख अंशः–

नया मंत्रालय बनने के बाद सहकारिता क्षेत्र की मजबूती के लिए जो पहल की गई है उसकी मौजूदा स्थिति क्या है?

मैं लंबे अरसे से सहकारिता को देखता और समझता रहा हूं और अब इस क्षेत्र के नीति निर्माण में शामिल हूं। देश में इस समय 8.54 लाख कोऑपरेटिव सोसायटी रजिस्टर्ड हैं जिनमें से 20 प्रतिशत क्रेडिट सोसायटी और बाकी नॉन-क्रेडिट सोसायटी हैं। अमूल, इफको, कृभको जैसी बड़ी कोऑपरेटिव दशकों से देश के कोऑपरेटिव सेक्टर को नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। मंत्रालय गठन के बाद से ही यह प्रयास किया जा रहा है कि जो छूटे हुए क्षेत्र हैं या कमजोर क्षेत्र हैं उनमें कोऑपरेटिव को कैसे मजबूत किया जाए। क्रेडिट सोसायटी, जिनमें पैक्स, ग्रामीण सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक आते हैं, उनमें एनपीए (गैर-निष्पादित संपत्तियां) की समस्या बहुत ज्यादा थी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस समस्या के समाधान और पैक्स को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए नीति बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी थी। इसके लिए जो कदम उठाए गए हैं उससे क्रेडिट कोऑपरेटिव के एनपीए पर काफी हद तक काबू पाया जा सका है।

पैक्स को मजबूत बनाने के लिए जो पहल की गई है उसका जमीनी स्तर पर कितना असर हुआ है?

जैसा कि सभी जानते हैं कि प्राथमिक सहकारी समिति (पैक्स) पहले केवल ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को छोटी अवधि के कर्ज देने, एग्रीकल्चर इनपुट मुहैया कराने और अनाजों की खरीद का काम करते थे। मंत्रालय के गठन के बाद पैक्स को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए मॉडल बायलॉज में संशोधन किया गया और उन्हें दो दर्जन से ज्यादा कारोबार करने की अनुमति दी गई। इस बायलॉज को 25 से ज्यादा राज्यों ने स्वीकार कर लागू कर दिया है। अब पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) चला रहे हैं, जन औषधि केंद्र, किसान समृद्धि केंद्र, पेट्रोल पंप खोल रहे हैं, अनाज भंडारण योजना के तहत अनाजों के गोदाम और अनाज खरीद केंद्र आदि बना रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखा जा रहा है जिसका फायदा किसानों और ग्रामीण आबादी को भी मिलने लगा है और वे समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 लागू होने के बाद इसका कोऑपरेटिव से जुड़े और आम लोगों को क्या फायदा होगा?

सहकार की भावना हमारे देश में नई नहीं है। इसका समावेशन हमारी संस्कृति में सदियों से है। वसुधैव कुटुम्बकम का जो भारत का नारा है वह सहकार का ही एक प्रतिबिंब है और सहकारिता इसका एक रूप है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के छह स्तंभ हैं। इसमें युवाओं को सहकारिता से जोड़ने और सहकारिता के माध्यम से उनका भविष्य संवारने के उपाय किए गए हैं। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि इस बात की संपूर्ण समीक्षा की जाए कि युवाओं को आगे बढ़ाने के क्या उपाय किए गए हैं, कोऑपरेटिव्स के लीडरशिप में उनकी कितनी भूमिका है, सहकारी संस्थाओं के निदेशक मंडल में किस तरह का व्यवहार किया जाता है, उनका गवर्नेंस कैसा है, जिम्मेदारी तय की जाती है या नहीं, राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं से पैक्स किस तरह से जुड़े हैं और उनका क्या और कितना योगदान है। इस तरह की समीक्षा नहीं की जाएगी तो यह क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाएगा।

भारत युवाओं का देश है। अगर कोऑपरेटिव्स युवाओं को आकर्षित नहीं कर पाएंगे तो नई नीति के जो छह स्तंभ हैं वे ढह जाएंगे। युवाओं को आकर्षित करने के लिए केवल कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि कोऑपरेटिव एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से कैसे युवाओं का भविष्य संवारा जा सकता है इसे भी देखना पड़ेगा और उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव्स उनके लिए कैसे लाभदायक हैं।

कोऑपरेटिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। पहले से भी कुछ एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देश में मौजूद हैं। क्या ये कोऑपरेटिव सेक्टर की कुशल पेशेवरों की जरूरतों को पूरी करने में सक्षम हैं?

आपने बहुत सही सवाल पूछा है। यह कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए बहुत नाजुक समय है। ईमानदारी से कहूं, तो आज युवाओं में सहकार की भावना तो है लेकिन वे सहकारिता क्षेत्र से दूर चले गए हैं। उनको सहकारी सिद्धांतों के माध्यम से इस क्षेत्र में लाना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें समझाना और जागरूक करना होगा कि आखिर यह है क्या और इस क्षेत्र में वे अपना करियर कैसे बना सकते हैं। एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से ही इस क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा कुशल पेशेवरों को तैयार किया जा सकता है। सहकारिता राज्य का विषय है। राज्यों को भी इसे बढ़ावा देने के लिए काफी सुधार और मेहनत करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कई राज्यों में नया कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए मेंबर्स की संख्या 50 तक होना जरूरी है। जम्मू-कश्मीर में तो 100 सदस्यों की अनिवार्यता है। इसी तरह, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा सभी राज्यों में नहीं है। इस तरह के कई प्रावधानों में राज्य स्तर पर बदलाव की जरूरत है। एजुकेशन एवं ट्रेनिंग और मानव संसाधन के लिए नीति बनाने, टेक्नोलॉजी को अपनाने जैसे उन्हें उपाय करने होंगे।■

सहकार की भावना हमारे देश में नई नहीं है। इसका समावेशन हमारी संस्कृति में सदियों से है। वसुधैव कुटुम्बकम का जो भारत का नारा है वह सहकार का ही एक प्रतिबिंब है और सहकारिता इसका एक रूप है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के छह स्तंभ हैं। इसमें युवाओं को सहकारिता से जोड़ने और सहकारिता के माध्यम से उनका भविष्य संवारने के उपाय किए गए हैं।

सहकारिता में भी डिजिटल हुआ पेमेंट, लोन सिस्टम

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन ऐप, डिजिटल क्रांति में सहकारिता की भागीदारी के बनेंगे प्रतीक

ये डिजिटल प्लेटफॉर्म सहकारी समितियों को पारदर्शी और कैशलेस लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के साथ लोन एवं क्रेडिट सिस्टम को बनाएंगे आसान

युवा सहकार टीम

पैक्स सहित सभी कोऑपरेटिव सोसायटी का कंप्यूटराइजेशन किए जाने से कोऑपरेटिव सेक्टर को डिजिटलाज्ड करना आसान हो गया है। इसी कड़ी में आगे कदम बढ़ाते हुए पेमेंट और लोन सिस्टम को डिजिटल बनाने की पहल की गई है। इसके लिए 'सहकार डिजी पे' ऐप और 'सहकार डिजी लोन' ऐप को लॉन्च किया गया है। डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन सिस्टम आज की जरूरत बन चुका है। कोऑपरेटिव सेक्टर डिजिटल दुनिया में पीछे न रह जाए, इसे देखते हुए ही यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को-ऑप कुंभ 2025 का उद्घाटन करते हुए इसे लॉन्च किया। इस सम्मेलन का आयोजन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अंब्रेला संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड (नैफकब) ने किया। इस सम्मेलन का थीम 'डिजिटलाइजिंग ड्रिम्स- सशक्त समुदाय' रखा गया था। को-ऑप कुंभ 2025 के दौरान पॉलिसी, तकनीक और इनोवेशन के विषय पर इस क्षेत्र से जुड़ी कई संभावनाओं का दोहन करने लिए विचार किया गया। साथ ही, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के विस्तार का रोडमैप तैयार करने के लिए 'दिल्ली घोषणा 2025' को प्रस्तुत किया गया।

'सहकार डिजी पे' एक ऐसा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जो सहकारी समितियों को पारदर्शी और कैशलेस लेनदेन की सुविधा प्रदान करेगा। यह प्लेटफॉर्म भीम यूपीआई द्वारा संचालित होगा, जिससे सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता और विश्वास को नई मजबूती मिलेगी। जिनका बैंक खाता कोऑपरेटिव बैंकों में है उनके लिए भी अब डिजिटल पेमेंट आसान हो जाएगा। अभी कोऑपरेटिव बैंकों के ज्यादातर खाताधारक इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि बहुत कम ऐसे कोऑपरेटिव बैंक हैं जो डिजिटल पेमेंट की सेवा दे रहे हैं। इससे जल्दी ही 800 से अधिक टियर-1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जुड़ जाएंगे। देश के 1,480 अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में से लगभग 80 प्रतिशत टियर-1 और टियर-2 श्रेणियों में आते हैं। इस ऐप से सिर्फ शहरी ही नहीं, दूरदराज के छोटे कोऑपरेटिव बैंकों और उनके ग्राहकों को भी सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

जबकि 'सहकार डिजी लोन' ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो देशभर के सहकारी सदस्यों को कागज रहित, त्वरित और पारदर्शी ऋण एवं क्रेडिट सुविधा प्रदान करेगा। सहकारी बैंकों एवं क्रेडिट सोसायटियों से लोन लेना अब सदस्यों के लिए आसान हो जाएगा। अभी उन्हें इनसे लोन लेने के लिए लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसमें समय भी ज्यादा लगता है। सहकार डिजी लोन ऐप के माध्यम से घर बैठे लोन के लिए आवेदन किया जा सकेगा और उन्हें इसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी। इन दोनों ऐप का विकास नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनयूसीएफडीसी) ने किया है और यही इसका संचालन भी करेगी। कोऑपरेटिव सेक्टर में डिजिटल क्रांति से सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर सहकारी आंदोलन को बढ़ावा मिलेगा।

हर शहर में खुलेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक- अमित शाह

इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट सोसायटी के सहकारिता कुंभ का आयोजन अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया है। पिछले 3-4 साल में देश का अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग क्षेत्र और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी क्षेत्र नए उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अगले पांच वर्षों के भीतर दो लाख से अधिक आबादी वाले हर कस्बे में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्थापित करने का लक्ष्य

'सहकार डिजी पे' एक ऐसा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जो सहकारी समितियों को पारदर्शी और कैशलेस लेनदेन की सुविधा प्रदान करेगा। यह प्लेटफॉर्म भीम यूपीआई द्वारा संचालित होगा, जिससे सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता और विश्वास को नई मजबूती मिलेगी। जिनका बैंक खाता कोऑपरेटिव बैंकों में है उनके लिए भी अब डिजिटल पेमेंट आसान हो जाएगा।

कॉप कुम्भ

रखा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को महत्वाकांक्षी युवाओं और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से सरकार ने कोऑपरेटिव से जुड़े हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए हैं। इसके साथ-साथ सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक बनाने, इसकी समस्याओं का समाधान करने और कोऑपरेटिव की पहुंच बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के लिए चार लक्ष्य तय किए हैं। जेनरेशन सहकार का विकास, यानी युवा पीढ़ी को सहकारिता के साथ जोड़ना। इसके लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई गई है जो सहकारिता क्षेत्र की हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करेगी। इसी तरह, हर प्रकार की चुनौतियों का सामना कर पाने वाली सहकारी समितियों को भी तैयार करने और अगले 5 वर्ष में 2 लाख से अधिक आबादी वाले हर शहर में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को अपना प्रमुख काम मल्टी-सेक्टर अप्रोच के साथ देश के युवा उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और कमजोर तबके के लोगों के सशक्तीकरण के लिए करना होगा। कोऑपरेटिव को मजबूत करने के साथ-साथ कमजोर तबके के लोगों को भी मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता।

अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को अपना प्रमुख काम मल्टी-सेक्टर अप्रोच के साथ देश के युवा उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और कमजोर तबके के लोगों के सशक्तीकरण के लिए करना होगा। कोऑपरेटिव को मजबूत करने के साथ-साथ कमजोर तबके के लोगों को भी मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंकों ने पिछले दो साल में एनपीए (गैर निष्पादित संपत्तियों) को 2.8 प्रतिशत से घटाकर 0.06 प्रतिशत करने में सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही अब संचालन के स्तर में सुधार करना होगा और वित्तीय अनुशासन में आए सुधार को आगे बढ़ाना होगा। हर शहर में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाना तभी संभव है जब कोऑपरेटिव सोसायटी को बैंक में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा।

कॉरपोरेट बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर रहे कोऑपरेटिव बैंक

नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनयूसीएफडीसी) के चेयरमैन ज्योतिंद्र मेहता ने अपने संबोधन में देश के कोऑपरेटिव बैंकिंग क्षेत्र के परिवर्तन, लचीलेपन और नए आत्मविश्वास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, 'अब वह दिन बीत चुके हैं जब सहकारी समितियों को दोयम दर्जे का माना जाता था। अब हम कॉरपोरेट क्षेत्र के साथ गर्व से खड़े हैं।'

विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के नेतृत्व में भारत की बैंकिंग प्रणाली को सबसे लचीली प्रणालियों में से एक माना गया है, मेहता ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, '2021 में हमारा ग्रॉस एनपीए लगभग 21 प्रतिशत था जो आज 7 प्रतिशत पर आ गया है। जबकि शुद्ध एनपीए केवल 1.2 प्रतिशत है।'

कॉप कुम्भ

नए क्षेत्रों में अवसर तलाशें सहकारी समितियां- सुरेश प्रभु

इस सम्मेलन को पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन सुरेश प्रभु ने भी संबोधित किया। उन्होंने अमित शाह के नेतृत्व में एक समर्पित सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के लिए सरकार की सराहना करते हुए इसे समावेशी और सतत विकास की दिशा में एक दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि सहकारिता राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों ने अपनी सहकारिता नीतियों का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अन्य राज्यों से भी विधायी और संरचनात्मक सुधारों के साथ ऐसा ही करने का आग्रह किया। नए क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए सुरेश प्रभु ने सहकारी समितियों को बांस आधारित उद्योगों और अन्य स्थायी उपक्रमों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया और इस आंदोलन में युवाओं और महिलाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है।

सम्मेलन के समापन सत्र में नैफकब के उपाध्यक्ष मिलिंद काले ने 'दिल्ली घोषणा-पत्र 2025' प्रस्तुत किया जिसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों और क्रेडिट सोसायटियों से अनुपालन को मजबूत करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और डिजिटल गवर्नेंस को अपनाने का आह्वान किया गया। घोषणा-पत्र में साइबर सुरक्षा, डेटा रिपॉजिटरी, ग्रीन फाइनेंस और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला गया और इस बात पर जोर दिया गया कि सहकारी समितियां केवल ऋण प्रदाता ही नहीं हैं, बल्कि सशक्तीकरण और आपसी विश्वास का माध्यम भी हैं।

अमित शाह के 'एक शहर, एक शहरी सहकारी बैंक' के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए ज्योतिंद्र मेहता ने कहा कि यह पहल अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के संतुलित भौगोलिक विकास को सुनिश्चित करेगी और क्षेत्रीय केंद्रीकरण को रोकेगी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भारत का अंब्रेला संगठन जल्द ही दुनिया भर की समान संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। एनयूसीएफडीसी कोऑपरेटिव बैंकिंग की डिजिटल रीढ़ होगी जो मजबूत, सुरक्षित और जन-केंद्रित होगी।'

डिजिटल क्रांति से मजबूत होगा सहकारी आंदोलन

अंब्रेला संगठन को सहकारिता की अगली सदी की ओर पहला कदम बताते हुए मेहता ने कहा कि यह इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक संरचनात्मक, वित्तीय और डिजिटल आधार प्रदान करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि को-ऑप कुंभ 2025 सहकारी ऋण आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। टेक्नोलॉजी और एकजुटता भारतीय सहकारी समितियों के भविष्य को परिभाषित करेंगे और इस एकता के माध्यम से हम एक मजबूत, अधिक समावेशी और डिजिटल रूप से सशक्त सहकारी भारत का निर्माण करेंगे।

वित्तीय समावेशन को नवाचार से जोड़ना समय की मांग

कर्नाटक के विधि, पर्यटन एवं संसदीय कार्य मंत्री और नैफकॉब के मानद अध्यक्ष डॉ. एच. के. पाटिल ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ और टिकाऊ बनाने के लिए नए नीतिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक से संकटग्रस्त बैंकों को बंद करने की मानसिकता छोड़ उनका पुनरुद्धार करने का आग्रह किया। समन्वित संस्थागत प्रयासों के माध्यम से यस बैंक के पुनरुद्धार का उदाहरण देते हुए उन्होंने संकटग्रस्त शहरी सहकारी बैंकों को बचाने के लिए इसी तरह के सहयोगात्मक दृष्टिकोण का सुझाव दिया। सम्मेलन के विषय, 'डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स, सशक्त समुदायों' पर प्रकाश डालते हुए डॉ. पाटिल ने कहा कि अगले दशक की मांग है कि सहकारी समितियां वित्तीय समावेशन को तकनीकी नवाचार के साथ जोड़ें। कोऑपरेटिव इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की पहलों की सराहना करते हुए उन्होंने कि सहकारिता मंत्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारी आंदोलन 'विश्वास, पारदर्शिता और परिवर्तन के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है।'■

को-ऑप कुंभ 2025 सहकारी ऋण आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। टेक्नोलॉजी और एकजुटता भारतीय सहकारी समितियों के भविष्य को परिभाषित करेंगे और इस एकता के माध्यम से हम एक मजबूत, अधिक समावेशी और डिजिटल रूप से सशक्त सहकारी भारत का निर्माण करेंगे।

एफपीओ समागम

बेहतर आजीविका के लिए फ्लिपकार्ट ने एफपीओ को सिखाए ई-कॉमर्स के गुर

छोटे किसानों को सशक्त बना रहे एफपीओ : शिवराज सिंह

केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय और फ्लिपकार्ट के सहयोग से आयोजित हुआ दो दिवसीय एफपीओ समागम सहयोग

फ्लिपकार्ट ने एफपीओ को सतत विकास और बेहतर आजीविका के लिए ई-कॉमर्स का लाभ उठाने का दिया प्रशिक्षण

युवा सहकार टीम

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से छोटे किसानों और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। किसानों की आय और पैदावार बढ़ाने, खेती की लागत घटाने, मूल्य संवर्धन और उचित बाजार मूल्य दिलाने के उद्देश्य से देशभर में 10 हजार एफपीओ का गठन किया गया है। अभी इनसे 52 लाख किसान जुड़े हुए हैं। अगले चरण में इनसे 2 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है जिनमें 50 प्रतिशत भागीदारी महिला किसानों की होगी। ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर गांवों को बढ़ावा देने में एफपीओ की भूमिका की समीक्षा करने और भविष्य का रोडमैप तय करने के लिए 30-31 अक्टूबर को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने घरेलू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के सहयोग से एफपीओ समागम का आयोजन किया गया। इसका उद्‌घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया।

इस पहल से पूरे भारत के एफपीओ और छोटे किसानों को अपनी मार्केटिंग क्षमताओं को बढ़ाने, डिजिटल क्षमता का निर्माण करने और ई-कॉमर्स के माध्यम से नए अवसरों को खोलने के लिए उन्हें एक साथ लाना संभव हो सका। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को उत्पादक से उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण, स्वदेशी पहलों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में एफपीओ की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने एफपीओ से आह्वान किया कि वे किसानों को केवल उत्पादक तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें व्यापारी और उद्यमी बनाएं। किसान प्रोसेसिंग करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। वैल्यू एडिशन की तरफ तेजी से बढ़ना होगा ताकि फसल का पूरा लाभ सीधे किसानों तक पहुंच सके। छोटे किसानों को सशक्त बनाने में एफपीओ प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। सरकार का उद्देश्य केवल एफपीओ का गठन करना ही नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाना भी है।

चौहान ने बताया कि देश के 1,100 एफपीओ करोड़ों रुपये के कारोबार तक पहुंच चुके हैं। इनमें से कुछ 100 करोड़ रुपये से अधिक के उद्यम बन चुके हैं। यह सामूहिक शक्ति और संगठनात्मक क्षमता का परिणाम है। उन्होंने किसानों से एफपीओ को गुणवत्ता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता के आधार पर मजबूत करने की अपील की। शिवराज सिंह ने ऐलान करते हुए कहा कि नकली और घटिया गुणवत्ता वाले बीजों और कीटनाशकों की बिक्री पर शिकंजा कसने के लिए सरकार जल्द ही एक नया सीड एक्ट लाने की तैयारी में है। सरकार इस मामले में सख्त है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए कड़ा कानून लाया जाएगा जिससे उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मिल सकें। उन्होंने कहा कि एफपीओ को खाद, बीज और कीटनाशक के लाइसेंस अधिक संख्या में दिए जाएंगे, ताकि वे थोक में कृषि इनपुट की खरीदारी

कर किसानों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करा सकें। इससे उत्पादन लागत घटेगी और लाभ बढ़ेगा। इंटिग्रेटेड खेती पर फोकस करके किसानों की आय में स्थायी वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अकेले अनाज नहीं, बल्कि बागवानी, डेयरी, मछली पालन और प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों को भी खेती से जोड़ा जाएगा।

फ्लिपकार्ट समूह के कॉरपोरेट मामलों के मुख्य अधिकारी रजनीश कुमार ने कहा, 'भारत का कृषि क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। फ्लिपकार्ट में हमें तकनीक, पारदर्शी सोर्सिंग और स्थायी साझेदारियों के माध्यम से व्यापक बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करके किसानों और एफपीओ का समर्थन करने पर गर्व है। हमारा लक्ष्य एक समावेशी, कुशल कृषि से उपभोक्ता बाजार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो किसानों की आय और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाए और एक आत्मनिर्भर भारत में योगदान दे।'

इस कार्यक्रम में एफपीओ के लिए गुणवत्ता संवर्धन, मूल्य संवर्धन और डिजिटल बाजार

शिवराज सिंह ने ऐलान करते हुए कहा कि नकली और घटिया गुणवत्ता वाले बीजों और कीटनाशकों की बिक्री पर शिकंजा कसने के लिए सरकार जल्द ही एक नया सीड एक्ट लाने की तैयारी में है। सरकार इस मामले में सख्त है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए कड़ा कानून लाया जाएगा जिससे उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मिल सकें।

तक उनकी पहुंच पर केंद्रित क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए गए। फ्लिपकार्ट ने भाग लेने वाले किसान संगठनों को यह समझने में मदद करने के लिए एक समर्पित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया कि वे डिजिटल बाजार का लाभ उठाकर व्यापक उपभोक्ता आधार तक कैसे पहुंच सकते हैं। इस दौरान क्रेता-विक्रेता संवाद भी आयोजित किया गया, जिसमें किसान संगठनों को नए व्यावसायिक अवसरों की खोज के लिए संभावित खरीदारों से जोड़ा गया।

यह सहयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और किसानों को बेहतर आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाने में मदद करेगा। निरंतर सरकारी समर्थन के साथ फ्लिपकार्ट का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पहुंच का विस्तार करना है, डिजिटल समावेशन और विस्तारित बाजार पहुंच के माध्यम से अधिक किसानों को सशक्त बनाना है।

दिल्ली के एनसीडीसी एवं एनसीयूआई परिसर में आयोजित इस समागम में 24 राज्यों और 140 जिलों के 500 से अधिक प्रगतिशील किसानों, एफपीओ और संबंधित एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उत्कृष्ट एफपीओ, सीबीबीओ और एजेंसियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर एक भव्य प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें 267 एफपीओ ने अनाज, तिलहन, दालों, फलों और सब्जियों सहित अपने विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया। कृषि मंत्री ने इन स्टॉलों का दौरा कर किसानों से सीधा संवाद किया और उनके नवाचारों की सराहना की।■

पीएम सेतु से उन्नत होंगे आईटीआई

युवा सहकार टीम

आईटीआई को उन्नत बनाने और उन्हें उद्योगों के साथ अधिक मजबूती से एकीकृत करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये की पीएम सेतु योजना की शुरुआत की गई है। इससे देश भर के 1,000 से अधिक आईटीआई संस्थान और वहां पढ़ने वाले लाखों छात्र लाभान्वित होंगे। इस पहल से आईटीआई को नई मशीनरी, उद्योग प्रशिक्षण विशेषज्ञों और वर्तमान एवं भविष्य की कौशल मांगों के अनुरूप पाठ्यक्रम के साथ उन्नत किया जाएगा। पीएम सेतु योजना भारतीय युवाओं को वैश्विक कौशल आवश्यकताओं से भी जोड़ेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आईटीआई छात्रों के लिए आयोजित दीक्षांत समारोह में इस योजना की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने 2000 करोड़ रुपये की अन्य योजनाओं का भी शुभारंभ किया जिनमें नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1,200 कौशल प्रयोगशालाओं और बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल तैयार करने के लिए उद्योग की जरूरतों के मुताबिक पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। इस दौरान आईटीआई के 46 टॉपरों को सम्मानित भी किया गया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, 'आईटीआई न केवल औद्योगिक शिक्षा के प्रमुख संस्थान हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कार्यशालाओं के रूप में भी काम करते हैं। सरकार आईटीआई की संख्या बढ़ाने और उन्हें निरंतर उन्नत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष 2014 तक देश में केवल 10,000 आईटीआई थे लेकिन पिछले एक दशक में लगभग 5,000 नए आईटीआई स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में आईटीआई लगभग 170 ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पिछले 11 वर्षों में 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने इन विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी योग्यताएं प्राप्त की हैं। आईटीआई नेटवर्क को वर्तमान उद्योग कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने और अगले 10 वर्षों में भविष्य की मांगों का अनुमान लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस दिशा में उद्योग और आईटीआई के बीच समन्वय बढ़ाया जा रहा है।'

पीएम सेतु योजना के तहत देश भर में 1,000 सरकारी आईटीआई को हब एंड स्पोक

प्रधानमंत्री ने पीएम सेतु योजना की शुरुआत की, 60,000 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड होंगे देश भर के 1,000 आईटीआई

नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1,200 कौशल प्रयोगशालाओं और बिहार के कौशल विश्वविद्यालय का भी किया उद्घाटन

> **प्रधानमंत्री ने 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया। ये प्रयोगशालाएं दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों सहित आईटी, ऑटोमोटिव, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन जैसे 12 उच्च मांग वाले क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगी।**

मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा। इसमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। प्रत्येक हब चार स्पोक से जुड़ा होगा, जिससे उन्नत बुनियादी ढांचे, आधुनिक ट्रेडों, डिजिटल लर्निंग सिस्टम और इनक्यूबेशन सुविधाओं से लैस क्लस्टर बनेंगे। उद्योग जगत को भी इससे जोड़ा जाएगा जो इन क्लस्टरों का प्रबंधन करेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजार की मांग के अनुरूप परिणाम आधारित कौशल विकास हो। हब में नवाचार केंद्र, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं, उत्पादन इकाइयां और प्लेसमेंट सेवाएं भी होंगी। योजना के कार्यान्वयन के प्रथम चरण में पटना और दरभंगा के आईटीआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया। ये प्रयोगशालाएं दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों सहित आईटी, ऑटोमोटिव, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन जैसे 12 उच्च मांग वाले क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप इस परियोजना में उद्योग प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने और रोजगार के लिए प्रारंभिक आधार तैयार करने हेतु 1,200 व्यावसायिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करना भी शामिल है।

इस कार्यक्रम का विशेष जोर बिहार में परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर होगा जो राज्य की समृद्ध विरासत और युवा जनसांख्यिकी को प्रतिबिंबित करेगा। प्रधानमंत्री ने बिहार की पुनर्निर्मित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ किया जिसके तहत हर साल लगभग पांच लाख स्नातक युवाओं को दो साल के लिए 1,000 रुपये का मासिक भत्ता और मुफ्त कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने पुनः डिजाइन की गई बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का भी शुभारंभ किया जो 4 लाख रुपये तक के पूरी तरह से ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करेगी। इससे उच्च शिक्षा का वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा। इस योजना के तहत 3.92 लाख से अधिक छात्रों ने पहले ही 7,880 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्राप्त किए हैं। साथ ही, छात्रों की छात्रवृत्ति राशि को 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,600 रुपये करने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की। राज्य में युवा सशक्तीकरण को और मजबूत करने के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए एक वैधानिक आयोग एवं बिहार युवा आयोग का औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया ताकि राज्य की युवा आबादी की ऊर्जा को दिशा दी जा सके।

उच्च शिक्षा के अवसरों को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने पीएम उषा (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान) के अंतर्गत बिहार के चार विश्वविद्यालयों- पटना विश्वविद्यालय, मधेपुरा स्थित भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, छपरा स्थित जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय और पटना स्थित नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखी। कुल 160 करोड़ रुपये के आवंटन वाली ये परियोजनाएं आधुनिक शैक्षणिक अवसंरचना, उन्नत प्रयोगशालाओं, छात्रावासों और बहु-विषयक शिक्षण को सक्षम बनाकर 27,000 से अधिक छात्रों को लाभान्वित करेंगी।

प्रधानमंत्री ने एनआईटी पटना के बिहटा परिसर को भी राष्ट्र को समर्पित किया। 6,500 छात्रों की क्षमता वाले इस परिसर में 5जी यूज केस लैब, इसरो के सहयोग से स्थापित एक क्षेत्रीय अंतरिक्ष शैक्षणिक केंद्र और एक नवाचार एवं इनक्यूबेशन केंद्र सहित उन्नत सुविधाएं मौजूद हैं।■

छोरियों ने दिखाया गिर कर उठना

सत्येन्द्र पाल सिंह

हरमनप्रीत कौर की अगुआई में भारत ने महिला वन डे विश्व कप 2025 जीत कर क्रिकेट का शिखर चूम कामयाबी की अदभुत दास्तां लिखी। इससे आने वाली पीढ़ी की हर बेटी के मन में क्रिकेट की ऐसी प्रीत जगेगी कि वह दुनिया में इसका डंका बजा निरंतर तिरंगा लहराने को तत्पर दिखेगी। इस कामयाबी के लिए इन सभी के पिताओं को पहले खुद से लड़ अपनी जिद छोड़ उन्हें अपना जुनून पूरा करने की इजाजत देने के लिए सलाम। भारत की बेटियों की इस कामयाब क्रिकेट यात्रा में उनकी माताओं, भाइयों और बहनों के त्याग को भी नमन। इन सभी महिला क्रिकेटरों के उस्तादों को सभी के क्रिकेट कौशल को तराशने के लिए साधुवाद। हरमनप्रीत कौर ने विश्व कप जीतने पर दंडवत हो जिस तरह चीफ कोच अमोल मजूमदार के पैर छुए उससे फिर दिखा कि आज भी देश की पुरातन गुरु-शिष्य परंपरा जीवित है। यह पूरी टीम द्वारा उनके प्रति आभार जताना भी था। यह परंपरा आगे भी बनी रहनी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला क्रिकेट टीम को अपने आवास पर आमंत्रित कर सम्मानित किया। इस दौरान कप्तान हरमनप्रीत ने प्रधानमंत्री से कहा, '2017 में हम जब आपसे मिले थे ट्रॉफी लेकर नहीं आ पाए थे, अब ट्रॉफी लेकर आए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम आपके साथ बार-बार ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवाएं।' वहीं प्रधानमंत्री ने टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित की गई दीप्ति शर्मा से उनके भगवान हनुमान वाले टैटू की बाबत पूछा, तो उन्होंने कहा, 'मुझे खुद से ज्यादा विश्वास भगवान पर है। मुश्किल समय में मैं भगवान को याद करती हूं, तो मुझे लगता है मैं इससे उबर सकती हूं।'

तीन हार के बाद लगातार तीन जीत से भारत चैंपियन

विश्व कप टूर्नामेंट में शुरु के दो मैच जीतने के बाद लगातार तीन करीबी मैच हारने के बाद उपकप्तान स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल की सलामी जोड़ी के शतकों से अहम लीग मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 59 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। जेमिमा रॉड्रिग्ज के शतक और कप्तान हरमनप्रीत कौर के अर्द्धशतक से भारत ने सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हरा फाइनल में जगह बनाई। शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा के बल्ले व गेंद से कमाल की बदौलत फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत के साथ महिला वन डे क्रिकेट विश्व कप खिताब जीत लिया। विश्व कप जीतने वाली इस टीम में जेमिमा रॉड्रिग्ज और प्रतीका रावल को छोड़कर बाकी 14 लड़कियां देश के दूरदराज के कस्बों और शहरों से आती हैं। जेमिमा मुंबई से,

> **भारत की बेटियों ने कप्तान हरमनप्रीत की अगुवाई में क्रिकेट वन डे विश्व कप जीत कर आलोचकों को दिया जवाब**

> **इससे पहले दो बार वन डे विश्व कप और एक बार टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी है महिला क्रिकेट टीम**

तो प्रतीका दिल्ली की रहने वाली हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर पंजाब के मोगा से हैं। विश्व कप में सबसे ज्यादा 22 विकेट चटकाने के साथ तीन अर्द्धशतक जड़ने वाली आगरा की दीप्ति शर्मा को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। वहीं शेफाली वर्मा हरियाणा के रोहतक की हैं। भारत की इन छोरियों ने दिखा दिया कि वे गिर कर फिर उठना खूब जानती हैं। ग्रामीण और कस्बाई परिवेश की इन लड़कियों के क्रिकेट खेलने पर जिस दकियानूसी समाज ने कभी ताने कसे थे, विश्व कप जीत कर उन्होंने उनकी सोच बदलने पर ऐसा मजबूर किया कि वे आज उन्हें पलकों पर बैठा रहे हैं।

भारत ने अब तक हुए 13 महिला वन डे क्रिकेट विश्व कपों में 1973 के पहले संस्करण और 1988 के चौथे संस्करण को छोड़ कर 11 में शिरकत की। भारत 2005 में मिताली राज की अगुआई में ऑस्ट्रेलिया से सेंचुरियन में फाइनल में 98 और 2017 में इंग्लैंड से लॉर्डस में मात्र 9 रन से हार वन डे विश्व कप जीतने से चूका। भारत तीन संस्करणों में चौथे स्थान पर रहा और 1997 में अपने घर में और 2000 में न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हारा। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में पुरुष वन डे क्रिकेट विश्व कप जीतने के 42 बरस बाद भारत ने पहली बार महिला वन डे क्रिकेट विश्व कप जीता है।

हरमनप्रीत की तमन्ना अब टी20 विश्व कप जिताने की

विश्व कप जीतने के बाद क्रिकेट समीक्षक महिला क्रिकेट टीम की तुलना 1983 में कपिलदेव की अगुवाई में पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम से कर रहे हैं। इस बाबत पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावसकर ने ठीक ही कहा कि 1983 में जब भारत ने वन डे विश्व कप जीत कर चमत्कार किया था तब टीम को छुपा रुस्तम इसलिए कहा गया था क्योंकि दुनिया के बड़े से बड़े समीक्षक तक ने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी। मिताली राज की कप्तानी में भारतीय महिला टीम 2005 और 2017 में वन डे विश्व कप के फाइनल में और 2020 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मेजबान ऑस्ट्रेलिया से टी20 क्रिकेट विश्व कप हार खिताब जीतने से चूक गई थी। भारतीय महिलाएं अब अगला वन डे विश्व कप 2029 में खेलेंगी। तब कप्तान हरमनप्रीत कौर 40 बरस की हो जाएंगी। तब हरमनप्रीत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना बहुत बड़ी चुनौती होगी। 2024 में पुरुष टी20 विश्व कप जिताने के बावजूद रोहित शर्मा के 2027 के पुरुष विश्व कप खेलने पर संदेह है। हरमनप्रीत कौर की तमन्ना अब बस अपना बल्ला टांगने से पहले महेंद्र सिंह धोनी की तरह वन डे के साथ टी20 विश्व कप भी जिताने की होगी। जुलाई 2026 में महिला टी20 विश्व कप आयोजित होगा। मौजूदा टीम में हरमनप्रीत कौर (36 वर्ष) को छोड़ बाकी 15 खिलाड़ियों की उम्र 30 बरस से कम है। अगले वन डे विश्व कप में बहुत मुमकिन है कि भारतीय महिलाएं स्मृति मंधाना की कप्तानी में खेलते दिखें।

टीम इंडिया में है हर गुलशन का फूल

इस विश्व विजेता टीम में आपको पंजाब के मोगा की हरमनप्रीत कौर, महाराष्ट्र के सांगली की स्मृति मंधाना, हरियाणा के रोहतक की शेफाली वर्मा, हिमाचल के रोहड़ू जैसे छोटे कस्बे की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर जैसी खिलाड़ी शामिल हैं। रेणुका ने अपने पिता को तीन बरस की आयु में ही खो दिया था। उसने मां द्वारा कपड़े से बनाई गेंद से खेलना शुरू किया था। आंध्र प्रदेश के कडप्पा की 21 बरस की बाएं हाथ की स्पिनर श्रीचारिणी, उत्तर प्रदेश के आगरा की दीप्ति शर्मा, बंगाल के सिलीगुड़ी से आने वाली विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष, देहरादून की स्नेह राणा, मध्य प्रदेश के छतरपुर के घुवारा के पुलिसकर्मी की बेटी तेज गेंदबाज क्रांति गौड़, मोहाली के बढ़ई की बेटी ऑलराउंडर अमनजोत कौर, मुंबई में सब्जी बेचने वाली की बेटी बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव, अपनी मां के समर्थन से क्रिकेट खेलने को साकार करने वाली तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी, बल्ले से धमाल के साथ अपने बैंड के कारण चर्चित मुंबई की जेमिमा रॉड्रिग्स और मनोविज्ञान में स्नातक एवं टीम में सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी प्रतीका रावल के रूप में टीम इंडिया में हर गुलशन के फूल के रूप में अनेकता में एकता की झलक साफ दिखाई देती है। दीप्ति के भाई ने उन्हें क्रिकेटर बनाने के लिए कॉरपोरेट की नौकरी तक छोड़ दी। हरमनप्रीत को क्रिकेटर बनाने के लिए पिता हरमंदर सिंह भुल्लर ने पड़ोसियों के ताने को नजरअंदाज कर पूरा समर्थन दिया और उन्हें काबिल कोच कमलदीश सिंह सोढ़ी को सौंपा।

स्मृति ने दाएं हाथ की होने के बावजूद बाएं हाथ के बल्लेबाज रहे अपने पिता श्रीनिवास मंधाना को देख बाएं हाथ की बल्लेबाज बनना तय किया। पिता श्रीनिवास ने अपनी बेटी के क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए घर में ही कंक्रीट की पिच बनवाई ताकि बड़े महानगरों से आने वाले क्रिकेटरों से उनकी बेटी पीछे न रह जाए। शेफाली वर्मा के पिता संजीव पेशे से सुनार हैं लेकिन खुद क्रिकेट के लिए बेहद जूनुनी हैं। शेफाली को लड़की होने के कारण अकादमी में प्रवेश नहीं मिला तो पिता ने उसके बाल कटवा दिए। ऋचा घोष के पिता मानवेंद्र घोष ने बेटी को क्रिकेटर बनाने के लिए कर्ज ही नहीं लिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया जो आखिर रंग लाया। अपना बल्ला न होने पर लड़कों ने अमनजोत कौर को खेलने नहीं दिया, तो उनके बढ़ई पिता भूपिंदर ने रात भर मेहनत कर उसके लिए बल्ला बनाया। इसके बाद तो उसने खूब क्रिकेट खेली। हरलीन जब चंडीगढ़ की गलियों में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती तो पड़ोसी ताना देते, लेकिन पिता बीएस देओल और मां चरणजीत कौर ने सबको दरकिनार कर बेटी को क्रिकेट खेलने को प्रेरित किया। पिता का ट्रांसफर हिमाचल होने से हरलीन को खुलकर क्रिकेट खेलने को मिला।

बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर सपोर्ट स्टाफ सहित 51 करोड़ रुपये बतौर इनाम देने की घोषणा की। खिताब जीतने पर आईसीसी से उसे करीब 40 करोड़ रुपये भी मिले। मध्य प्रदेश सरकार ने क्रांति गौड़ को और हिमाचल प्रदेश सरकार ने रेणुका सिंह ठाकुर को एक-एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

टीम इंडिया पर धनवर्षा

बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर सपोर्ट स्टाफ सहित 51 करोड़ रुपये बतौर इनाम देने की घोषणा की। खिताब जीतने पर आईसीसी से उसे करीब 40 करोड़ रुपये भी मिले। मध्य प्रदेश सरकार ने क्रांति गौड़ को और हिमाचल प्रदेश सरकार ने रेणुका सिंह ठाकुर को एक-एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की। वहीं पंजाब सरकार ने हरमनप्रीत कौर को 11 लाख रुपये और अमनजोत कौर एवं टीम इंडिया के फील्डिंग कोच मुनीश बाली को 5-5 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की।

टीम की कामयाबी का श्रेय क्रिकेट बोर्ड को

भारतीय महिला क्रिकेट के कायाकल्प का श्रेय सही मायनों में बीसीसीआई को दिया जाना चाहिए। भारतीय महिला क्रिकेट संघ (डब्ल्यूआईसीए) का गठन 1973 में हुआ था। महिला टीम को विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भेजने के लिए डब्ल्यूआईसीए बराबर जूझती रही। 2006 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के आदेश पर डब्ल्यूआईसीए के बीसीसीआई में विलय से भारतीय महिला क्रिकेट की दशा सुधरी। बीसीसीआई ने 2018 से महिला क्रिकेटरों के लिए सालाना कांट्रेक्ट शुरू किया। पुरुषों की आईपीएल की तर्ज पर 2023 में महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) शुरू हुआ। इससे भारत की महिला क्रिकेटरों को दुनिया भर की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के साथ और उनके खिलाफ विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों में खेलने का मौका मिलने से नाम के साथ खूब दाम भी मिला। इससे उनकी आर्थिक बदहाली बहुत हद तक दूर हो गई। इससे भारतीय महिला क्रिकेटरों का विदेशी क्रिकेटरों के खिलाफ खेलने का भय ही नहीं निकला, वे आज उन्हें हर मंच पर टक्कर देने लायक हो गई हैं। आज उन्हें टेस्ट मैच खेलने के लिए पुरुष क्रिकेटरों की ही तरह फीस के रूप में प्रति टेस्ट 15 लाख रुपये, वन डे इंटरनेशनल के लिए 6 लाख और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए प्रति मैच 3 लाख रुपये मिलते हैं।

बीसीसीआई ने 24 मार्च, 2025 से सीनियर क्रिकेटरों के लिए सालाना रिटेनरशिप तय कर उन्हें तीन ग्रेड ए, बी और सी में बांटा। ग्रेड ए की महिला क्रिकेटरों को सालना 50 लाख रुपये, ग्रेड बी को 30 लाख और ग्रेड सी की क्रिकटरों को 10 लाख रुपये सालाना दिए जा रहे हैं। ■

संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक

युवा सहकार टीम

जीवन में हर किसी के सपने होते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए साहस, अवसर और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ओडिशा की रहने वाली 32 वर्षीय भुवनेश्वरी भुइयां इसी सच्चाई की मिसाल हैं। मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाली भुवनेश्वरी ने स्नातक तक की पढ़ाई की। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते वह आगे की शिक्षा जारी नहीं रख सकीं। मगर उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने, खुद के पैरों पर खड़ा होने और परिवार की जिम्मेदारी में हाथ बंटाने का सपना पलता रहा।

आर्थिक तंगी के कारण कई बार सपने अधूरे रह जाते हैं। भुवनेश्वरी भी इसी कठिनाई से जूझ रही थीं। तभी उन्हें नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) की दिल्ली स्थित विकासपुरी शाखा द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के बारे में पता चला जहां इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के सीएसआर कार्यक्रम के सहयोग से सेल्फ इम्प्लॉयड टेलर और सीसीटीवी इन्स्टॉलेशन एवं टेक्निशियन के कोर्स कराए जाते हैं। ये कोर्स केवल तीन महीने के हैं। इन कोर्स की बुनियाद कौशल विकास है। यह कार्यक्रम युवाओं को निःशुल्क विभिन्न व्यावसायिक कौशल सिखाने के लिए चलाया जाता है। भुवनेश्वरी ने जब प्रशिक्षण केंद्र के कार्यक्रम समन्वयक से मुलाकात की तो उन्हें जीवन की एक नई दिशा मिली। उनके प्रोत्साहन और सहयोग से उन्होंने परिधान क्षेत्र के सेल्फ इम्प्लॉयड टेलर के तीन महीने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला लिया।

आईजीएल के सीएसआर कार्यक्रम के तहत एनवाईसीएस द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम से सशक्त हुई ओडिशा की भुवनेश्वरी भुइयां, चला रहीं खुद का बुटीक

प्रशिक्षण के दौरान उनकी प्रशिक्षिका शशि कला ने उन्हें सिलाई, डिजाइनिंग और वस्त्र निर्माण की बारीकियां सिखाईं। यह केवल तकनीकी शिक्षा नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम था। व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनका एनएसडीसी (नेशनल स्कील डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) द्वारा मूल्यांकन किया गया और उन्हें कौशल प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

सपनों को मिला अपना ब्रांड

प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रशिक्षण केंद्र की ओर से भुवनेश्वरी को नौकरी का अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को अलग राह दी। उन्होंने तय किया कि वह दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए काम करेंगी। इसी सोच ने जन्म दिया उनके अपने बुटीक 'मिट्टू कलेक्शन' को। आज भुवनेश्वरी का यह बुटीक उनकी मेहनत और हिम्मत का प्रतीक है। वह हर महीने लगभग 20,000 रुपये तक की आमदनी कर रही हैं। वह अब आर्थिक रूप से सक्षम हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अपने हुनर पर गर्व है।

कौशल विकास से आत्मनिर्भर हुईं भुवनेश्वरी ने युवा सहकार से कहा, 'मैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) और एनवाईसीएस का दिल से आभार व्यक्त करती हूं। इस प्रशिक्षण ने मुझे केवल कौशल नहीं, आत्मविश्वास भी दिया। आज मैं अपने परिवार की मदद कर पा रही हूं और अपने दम पर आगे बढ़ रही हूं।'

एनवाईसीएस उन अनगिनत महिलाओं के जीवन में नई रौशनी लेकर आई है जो कभी आर्थिक या सामाजिक कारणों से पीछे रह जाती थीं। यह पहल केवल प्रशिक्षण नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में उठाया गया सशक्त कदम है।■

NYCS
National Yuva Co-operative Society Limited

Empowering Financial Independence

Our Services
Loans: Small, medium, and large loans at highly competitive interest rates, catering to the diverse financial needs of our members.
Deposits: Attractive interest rates, with special benefits for senior citizens and women.
Simplified Process: Our streamlined application process and flexible terms ensure that financial assistance is always within reach.

Our Reach
- Presence in All States & Union Territories
- 37 Branches Nationwide
- 600+ Districts Served by Our Representatives
- Central Administration Office (CAO) in Pune, Led by Senior Banking & Finance Professionals

Why Choose NYCS Ltd.?
- Trusted Expertise – Over 20 years in financial services.
- Nationwide Presence – A rapidly growing network.
- Member-Focused – Tailored financial solutions.
- Youth Empowerment – Supporting young entrepreneurs.

Contact Us
209, 2nd Floor, A2B, Vardhman Janak Market, Janakpuri, New Delhi-58
+91 9205595944
011-45096652/40153681
nycs.ltd@gmail.com
www.nycsltd.com

Together, let's build a brighter financial future!

शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTRY OF EDUCATION
Government of India
सत्यमेव जयते

nbt.india
एकः सूते सकलम्
देश का नॉलेज पार्टनर

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत

द्वारा

आयोजित होने वाले आगामी पुस्तक मेले

गोरखपुर पुस्तक महोत्सव, उत्तर प्रदेश
1 से 9 नवंबर 2025

अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव, गुजरात
13 से 23 नवंबर 2025

नागपुर पुस्तक महोत्सव, महाराष्ट्र
22 से 30 नवंबर 2025

पुणे पुस्तक महोत्सव, महाराष्ट्र
13 से 21 दिसंबर 2025

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला
10 से 18 जनवरी 2026

संबलपुर पुस्तक मेला, ओडिशा
24 जनवरी से 1 फरवरी 2026

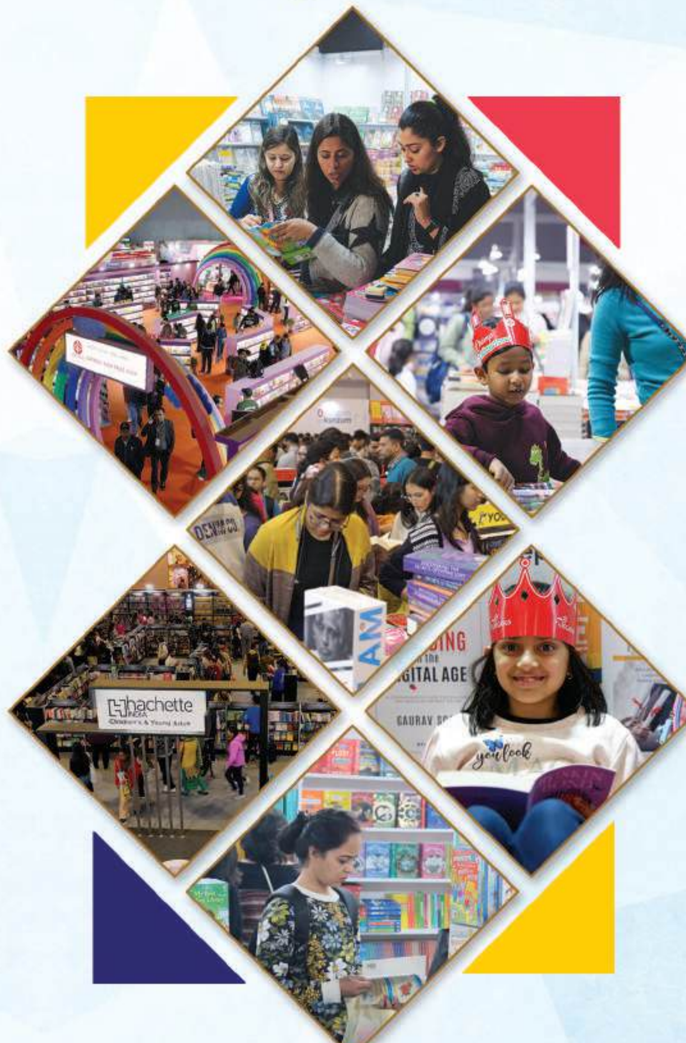

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें : nbtexhibition3@gmail.com

nbt.india
एकः सूते सकलम्
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
NATIONAL BOOK TRUST, INDIA
Ministry of Education, Government of India

5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, वसंत कुंज,
नई दिल्ली–110070
ईमेल : office.nbt@nic.in
वेबसाइट : www.nbtindia.gov.in

हमारी वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

नई दिल्ली | पुणे | बेंगलुरु | कोलकाता | चेन्नई | हैदराबाद | गुवाहाटी | अगरतला | पटना | कटक | कोच्चि | भोपाल | देहरादून | लखनऊ

Follow us on @nbt_india | instagram.com/nbtindia | YouTube youtube.com/nbtindia | fb.com/NationalBookTrustIndia